

## आधार को मतदाता सूची से जोड़ना स्वैच्छिक: ECI

### प्रलिस के लिये:

[आधार, भारत नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#)

### मेन्स के लिये:

मतदाता सूची को आधार से जोड़ने का प्रभाव

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) में एक याचिका के जवाब में [भारत के नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) ने स्पष्ट किया कि [आधार संख्या को मतदाता सूची के साथ जोड़ना](#) अनविर्य नहीं है।

### नोट:

- मतदाता सूची एक वशिष्ट क्षेत्राधिकार के तहत पात्र मतदाताओं की सूची है, जिसे ECI द्वारा तैयार और अद्यतन किया जाता है।

### आधार को मतदाता सूची से जोड़ने को लेकर चर्चाएँ:

#### दलील:

##### पृष्ठभूमि:

- एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर केंद्र और ECI को नामांकन के लिये आवेदन पत्र में संशोधन करने तथा मतदाता सूची के साथ [आधार संख्या](#) के प्रमाणीकरण के लिये भारत संघ द्वारा अधिसूचि संशोधि प्रावधानों/नयिमें पर **1 अप्रैल, 2023** या उससे पहले की मतदाता सूची को अद्यतन करने का नरिदेश दिये जाने का आग्रह किया।

##### चर्चाएँ:

- याचिकाकर्ता ने मतदाता गोपनीयता के बारे में चर्चा व्यक्त की और आरोप लगाया कि केंद्र और नरिवाचन आयोग वैकल्पिक विकल्प प्रदान किये बिना मतदाताओं को अपना आधार नंबर जमा करने के लिये मजबूर कर रहे हैं।

##### कानूनी रुख:

- इस प्रथा ने [संवधान](#) के [अनुच्छेद 14 और 21](#) का उल्लंघन किया और इससे मतदाताओं के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है।

#### सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में इस बात को दर्ज किया कि मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नयि 2022 के नयि 26-B के अनुसार आधार संख्या जमा करना अनविर्य नहीं है।

- "मौजूदा मतदाताओं द्वारा आधार संख्या प्रदान किये जाने के लिये वशिष प्रावधान" से संबंधि नयि 26B के अनुसार, "प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सूची में सूचीबद्ध है, वह [लोक प्रतनिधित्व अधिनयि, 1950](#) की धारा 23 की उपधारा (5) के अनुसार फॉर्म 6बी में पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचि कर सकता है।

- फॉर्म 6B एक सूचना पत्र है जिसमें मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से कसी व्यक्ति का आधार नंबर शामिल होता है।

#### भारत नरिवाचन आयोग (ECI) की प्रतिकरिया:

- ECI की प्रतिकरिया थी कि [आधार नंबर जमा करना स्वैच्छिक](#) है। चुनाव आयोग, आधार लकिज से संबंधि फॉर्मों में उचि स्पष्टीकरण

- परिवर्तन करने पर वचिार कर रहा है, जो आधार जमा करने की स्वेच्छक प्रकृती को स्पष्ट करने के उसके इरादे को दर्शाता है।
- चुनाव नकिय ने पीठ को सूचित किय कि "मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया मेलगभग 66.23 करोड आधार नंबर पहले ही अपलोड किय जा चुके हैं"।

## भारत नरिवाचन आयोग (ECI):

### ■ स्थापना एवं भूमिका:

- ECI की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी।
- यह एक स्वायत्त संविधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं की देख-रेख एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
- आयोग का सचिवालय नई दलिली में स्थिति है।
- ECI भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का प्रबंधन करता है। यह भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिये चुनावों की देख-रेख भी करता है।
- इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिये भारत का संविधान एक अलगराज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है।

### ■ ECI की संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय नकिय बना दिया गया।
  - मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्त (EC) भारत के चुनाव आयोग का गठन करते हैं।
    - CEC और EC का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
  - राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मदद मुख्य नरिवाचन अधिकारी द्वारा की जाती है जो IAS रैंक का अधिकारी होता है।

### ■ आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल:

- राष्ट्रपति CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है।
- उनका छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) का एक नश्चिति कार्यकाल होता है।

### ■ आयुक्तों का नषिकासन:

- आयुक्त स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है।

### ■ सीमाएँ:

- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) नरिधारित नहीं की गई है।
- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को नरिदषिट नहीं किय गया है।
- संविधान ने सेवानवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा करिी और नियुक्ति से वंचित नहीं किय है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजिय: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरकिता या अधविस के प्रमाण के रूप में किय जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात् इसे नरिगत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)